



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, झंगलबार, ४ अगस्त, १९९२/१३ अक्टूबर, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला १७१००२, ४ अगस्त, १९९२

संख्या एल० एल० आर०-डी० (६)२१/१२-लेजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपात्र, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख ३ अगस्त, १९९२ को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९९२ (१९९२ का अध्यादेश

संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
सचिव ।

1992 का अध्यादेश संख्यांक 2

## हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992

भारत गणराज्य के तैनालीसवें वर्ष में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1975 (1975 का 11) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि एसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है :

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 की धारा 3 में—

धारा 3 का संशोधन ।  
1975 का 11.

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) उपभोग की गई ऊर्जा पर “विद्युत शुल्क” कहा जाने वाला शुल्क विहित रीति में उद्गृहीत और सरकार को सदर्त किया जाएगा और निम्नलिखित दरों पर परिकलित किया जाएगा :—

- (i) घरेलू उपभोक्ताओं की दशा में पांच पैसे, प्रति यूनिट की दर से; और
- (ii) अन्य प्रवर्ग के उपभोक्ताओं की दशा में दस पैसे प्रति यूनिट की दर से :

परन्तु यदि ऊर्जा का अंशतः उक्त प्रवर्ग (i) और अंशतः प्रवर्ग (ii) के लिए उपभोग किया जाता है, तो शुल्क की उच्चतम लागू दर उद्गृहीत की जाएगी।”

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 11-क जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 11-क का जोड़ना ।

11-क छूट देने की शक्ति.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति को विद्युत शुल्क के पूर्णतः या अंशतः संदाय से, एसी अवधि के लिए और ऐसे निबन्धन और शर्तों के अधीन जो एसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लोकहित में, छूट दे सकेगी ।

वीरेन्द्र वर्मा,  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश ।

शिमला :

3 अगस्त, 1992.

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Ordinance No. 2 of 1992.

## THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1992

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fortythird year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975 (Act No. 11 of 1975).

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) (Second Amendment) Ordinance, 1992.

Amendment of section 3.

2. For sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975, hereinafter called the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy consumed a duty to be called the “electricity duty” in the prescribed manner and computed at the following rates:—

- (i) in case of domestic consumers at the rate of 5 paise per unit; and
- (ii) in case of other category of consumers at the rate of 10 paise per unit:

Provided that if the energy is partly used for category (i) and partly for category (ii) above, the highest rate of duty applicable will be levied.”

Addition of section 11-A.

3. After section 11 of the principal Act, the following section 11-A shall be added, namely:—

“11-A *Power to exempt.*—The State Government may in public interest by notification exempt any consumer or person from the payment of the whole or part of the electricity duty for such period and subject to such terms and conditions as may be specified in such notification.”

SHIMLA:  
3 August, 1992.

VIRENDER VERMA,  
Governor,  
Himachal Pradesh.